बिना संस्कार नहीं सहकार

बिना सहकार नहीं उद्धार

छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार

वर्ष- 23 अंक - 13 अक्टूबर 2026 प्रथम पाक्षिक RNI NO. CHHHIN/2012/45105 प्रकाशन तिथि 15 अक्टूबर पृष्ठ-12 मूल्य 2000/- वार्षिक

मैं से हम की यात्रा है सहकारिता - सौरभ शर्मा

सहकार से समृद्धि का राष्ट्रीय संदेश लेकर संपन्न हुई जगदलपुर में कार्यशाला







व्यापक बदलाव के लिए राज्यों से आवश्यकता अनुरूप कार्ययोजना बनाने का आह्वान

■ बस्तर में 9वीं राष्ट्रीय सहकारी समीक्षा कार्यशाला का समापन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र के सुधारों को जमीनी स्तर पर ठोस और मापनीय परिणामों में बदलने पर जोर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी बोले- राज्य प्राथमिकताएं निर्धारित कर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तय करें और नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें NCEL, NCOL और BBSSL के माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण, बेहतर बाजार पहुंच और लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के क्षेत्र में जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के लिए नए अवसरसहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने और युवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा, आधुनिक कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक राज्यों से नई PACS के गठन में तेजी लाने, सदस्यता विस्तार करने और व्यवहार्य जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए मजबूत आधार तैयार करने का आग्रह PACS कम्प्यूटरीकरण का पहला चरण दिसंबर 2026 तक और वित्त वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक पूरे के निर्देश।

बस्तर में सहकारिता विकास को मिली नई दिशा

विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण अवसंरचना के विस्तार और प्लेज फाइनेंस सहित किसानों के हित में वैकल्पिक विपणन एवं वित्तपोषण मॉडल विकसित करने पर जोर

जगदलपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय देश के सहकारी क्षेत्र को अधिक सशक्त, समावेशी, पारदर्शी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में सहकारिता मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 और 9 अक्टूबर 2026 को 'सहकार से समृद्धि – आगे की राहः सहकारिता रूपांतरण से व्यापक प्रभाव की ओर' विषय पर आयोजित दो दिवसीय 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला आज संपन्न हुई। कार्यशाला में सहकारिता क्षेत्र की सफल पहलों को जमीनी स्तर पर व्यावहारिक, समयबद्ध और मापनीय परिणामों में बदलने पर विशेष जोर दिया गया।

मंत्रालय की प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा

कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, सहकारिता पंजीयकों, राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं और संघों के प्रतिनिधियों तथा सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। दो दिनों के दौरान प्रतिभागियों ने मंत्रालय की प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा की, राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा किया तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), सहकारी बैंकिंग, डेयरी सहकारी संस्थाओं, डिजिटलीकरण, व्यवसाय विविधीकरण, सहकारी विपणन और विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण को मजबूत करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। कार्यशाला में पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी सीमांत क्षेत्रों के सहकारी विकास के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

कोई एक मॉडल पूरे देश में लागू नहीं हो सकता

समापन सत्र को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श को अत्यंत सार्थक और उपयोगी बताते हुए कहा कि, इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा अनेक नवाचारपूर्ण, व्यावहारिक और जिला-विशिष्ट पहलें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि, इस कार्यशाला की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह रही कि सहकारी विकास का कोई एक मॉडल पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक राज्य की अपनी परिस्थितियां, चुनौतियां, परंपराएं और संस्थागत आवश्यकताएं हैं, इसलिए सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में प्रस्तुत अनेक सफल कार्यप्रणालियां अन्य राज्यों में भी अपनाए जाने और व्यापक स्तर पर विस्तार दिए जाने योग्य हैं।

PACS की भूमिका बढ़ाने की संभावनाएं तलाशें

डॉ. भूटानी ने उर्वरक व्यवसाय से संबंधित योजनाओं पर हुए विचार-विमर्श की भी सराहना की और राज्यों से जहां भी व्यावहारिक रूप से संभव हो, इस क्षेत्र में PACS की भूमिका बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवहार्य व्यावसायिक अवसर विकसित करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी गतिविधियों में विविधता ला सकें, वित्तीय स्थिरता मजबूत कर सकें और अपने सदस्यों को अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर

सहकारी बैंकिंग से संबंधित सत्र का उल्लेख करते हुए सचिव ने विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए नवाचारों की सराहना की और कहा कि सहकारिता मंत्रालय, सहकारी बैंकों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निरंतर समन्वय कर रहा है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने, मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपाय अपनाने और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखने और अन्य बैंकिंग संस्थाओं के साथ प्रभावी प्रतिस्पर्धा के लिए सहकारी बैंकों को सुरक्षित और आधुनिक बैंकिंग अवसंरचना विकसित करनी होगी।

सफल मॉडलों का अध्ययन कर उन्हें अपनाएं

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की गतिविधियों पर प्रस्तुतियों का उल्लेख करते हुए सहकारिता सचिव ने कहा कि, अनेक राज्यों ने इन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं का प्रभावी उपयोग कर जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि, इन संस्थाओं के माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण, व्यापक बाजारों तक पहुंच और किसानों तथा सहकारी सदस्यों को लाभकारी मूल्य दिलाने के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में पिछले दो वर्षों से मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए अन्य राज्यों को भी कार्यशाला में प्रस्तुत सफल मॉडलों का अध्ययन कर उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

‹‹ शेष पेज 10 पर

मुलकानूर से कोथाकोंडा तक छत्तीसगढ़ के सहकारी प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन भ्रमण

■ दुग्ध सहकारिता, महिला सशक्तीकरण, बुनकर संघ और सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं की कार्यप्रणाली का लिया जायजा

वारंगल। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 15 अक्टूबर तक तेलंगाना के वारंगल एवं आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुलकानूर की सफल सहकारी व्यवस्था, दुग्ध सहकारिता, महिला सशक्तीकरण, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, बुनकर संघ तथा सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की।

12 अक्टूबर को प्रतिनिधिमंडल ने मुलकानूर सहकारी संस्था का भ्रमण कर अध्यक्ष श्री प्रदीप रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने संस्था की कार्यप्रणाली, सहकारी गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने



में इसकी भूमिका की जानकारी दी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने दुग्ध सहकारी संस्था (MSCD) का दौरा किया और दुग्ध व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी, आजीविका संवर्धन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों को समझा।

सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को देखा

13 अक्टूबर को प्रतिनिधिमंडल ने मां भद्रकाली मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मुलकानूर स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) का भ्रमण कर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। इसी दिन सदस्यों ने विश्व धरोहर रामप्पा मंदिर का भी भ्रमण किया और तेलंगाना की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया। अध्ययन भ्रमण के अंतिम चरण में प्रतिनिधिमंडल ने कोथाकोंडा स्थित WTC एवं AWTC का दौरा कर प्रशिक्षण गतिविधियों और संस्थागत कार्यप्रणाली पर चर्चा की। इसके साथ ही बुनकर संघ की गतिविधियों का अध्ययन किया तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी भ्रमण किया।

सफल सहकारी व्यवस्थाओं से सीखना था यात्रा का उद्देश्य

इस अध्ययन भ्रमण का उद्देश्य तेलंगाना की सफल सहकारी व्यवस्थाओं से अनुभव प्राप्त कर छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाने, प्रशिक्षण गतिविधियों को सुदृढ़ करने तथा महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण आजीविका और सहकारी उद्यमों के विकास की संभावनाओं को समझना था। ‹‹ शेष पेज 10 पर

भारत टैक्सी की पहली आमसभा में सहकारी मॉडल को मजबूत करने पर जोर



ड्राइवरों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ने और 'सहकार से समृद्धि' की दिशा में आगे बढ़ने की कार्ययोजना

नई दिल्ली। भारत टैक्सी की पहली वार्षिक आमसभा में सहकारी संस्था की अब तक की प्रगति की समीक्षा के साथ आगामी वर्ष की विकास रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में सहकारी परिवहन मॉडल को मजबूत करने, सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने और ड्राइवरों को सहकारी व्यवस्था से जोड़कर उन्हें बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में सहकारी मॉडल के माध्यम से परिवहन क्षेत्र में सामूहिक भागीदारी और सदस्य-आधारित विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई। भारत टैक्सी के माध्यम से ड्राइवरों को सहकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाकर उन्हें संगठनात्मक भागीदारी और व्यवसाय से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ने पर विचार किया गया।

प्रगति की हुई समीक्षा

आमसभा में वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और संस्था की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी वर्ष के लिए कार्ययोजना, प्राथमिकताओं, जिम्मेदारियों और लक्ष्यों पर चर्चा हुई। बैठक में सहकारिता के माध्यम से परिवहन क्षेत्र को संगठित एवं सशक्त बनाने की दिशा में 'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दिल्ली यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आमसभा में भाग लिया। इनमें विशेष आयुक्त अजय चौधरी, आईपीएस तथा भारत टैक्सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल हिमांशु प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

आमसभा में इन प्रतिनिधियों की रही भागीदारी

आमसभा में भारत टैक्सी के अध्यक्ष जयेन मेहता, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार बंसल तथा उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता सहित प्रमुख सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नेफेड, इफ्को, कृभको, एनडीडीबी, एनसीईएल और नाबार्ड के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।

बीबीएसएसएल का राजस्व 274.7 % प्रतिशत बढ़कर 222 करोड़ रुपये पहुंचा



- **एक साल में 59.25 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ रुपये हुआ राजस्व; सहकारी बीज कारोबार में तेज विस्तार**

नई दिल्ली। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। समिति का राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 के 59.25 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 222 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह एक वर्ष में राजस्व में 162.75 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी, अर्थात लगभग 274.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरे शब्दों में, समिति का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.75 गुना हो गया।

नई दिल्ली में आयोजित बीबीएसएसएल की चौथी वार्षिक आमसभा में समिति के वित्तीय प्रदर्शन, सदस्यता विस्तार, बीज उत्पादन तथा आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई। आमसभा में करीब 250 प्रतिनिधियों ने प्रत्यक्ष और 11,827 प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन भाग लिया।

38,665 सहकारी समितियां बनीं सदस्य

जुलाई 2026 तक बीबीएसएसएल से 38,665 सहकारी समितियां जुड़ चुकी थीं। इनमें 37,972 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) शामिल हैं। 'भारत बीज' ब्रांड के विस्तार के लिए 33 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने नोडल एजेंसियां नामित की हैं, जबकि 26 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

28 फसलों की 208 किस्में 'भारत बीज' के तहत

बीबीएसएसएल ने 'भारत बीज' ब्रांड के तहत 28 फसलों की 208 किस्मों के बीज पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में संबंधित बीज उत्पादक किसानों के माध्यम से 75,535 मीट्रिक टन बीज का उत्पादन किया गया।

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक से जुड़े तीन मामलों की धारा 62 के तहत जांच शुरू

आरसीएस ने सहायक आयुक्त हिमांशु रंजन को बनाया जांच अधिकारी, 30 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (आरसीएस) ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से जुड़े तीन मामलों की दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। आरसीएस ने 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश में हिमांशु रंजन, आईआरएस, सहायक आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।यह कार्रवाई 18 सितंबर 2020 को लालित कुमार द्वारा दायर शिकायत के आधार पर की गई है। इससे पहले इन मामलों का धारा 61 के तहत निरीक्षण किया जा चुका है।

धारा 61 के निरीक्षण के बाद जांच की सिफारिश

इन तीनों विषयों का पूर्व में के.एस. मीणा, आईएएस (सेवानिवृत्त) द्वारा धारा 61 के तहत निरीक्षण किया गया था। 3 जुलाई 2025 की निरीक्षण रिपोर्ट में धारा 62 के तहत विस्तृत जांच शुरू करने की सिफारिश की गई थी। बैंक एवं संबंधित निदेशकों ने निरीक्षण कार्यवाही को वित्तीय आयुक्त, जीएनसीटीडी के समक्ष चुनौती दी थी। वित्तीय आयुक्त ने 6 फरवरी 2026 के आदेश में धारा 61 के तहत किए गए निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, आरसीएस को धारा 62 के तहत जांच शुरू करने से पहले संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के निर्देश दिए गए।

तीन मामलों की होगी जांच

पहला मामला—शेयर खरीद के लिए ऋण: सदस्य सहकारी समितियों को बैंक के शेयर खरीदने के लिए दिए गए ऋण से संबंधित है। पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट में इन ऋणों के कारण बैंक की शेयर पूंजी में दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी कम होने से जुड़े प्रश्न उठाए गए थे।

दूसरा मामला—नांगलोई की भूमि: बैंक की नांगलोई स्थित करीब 715 वर्ग गज भूमि को दिल्ली कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सप्लाई फेडरेशन को कथित रूप से हस्तांतरित किए जाने से संबंधित है।

तीसरा मामला—भर्ती और फ्लैट खरीद: वर्ष 2009-10 में बैंक के अधिकारियों, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आदि के रिश्तेदारों की कथित अनियमित भर्ती तथा डीडीए के चार फ्लैटों की कथित 'ओपन बिड' के माध्यम से खरीद से जुड़ा है। पूर्व निरीक्षण में इन मामलों से बैंक को कथित वित्तीय नुकसान होने के मुद्दे का भी उल्लेख किया गया था।

डेयरी सहकारिता के विस्तार से बढ़ेगी पशुपालकों की आय: अमित शाह

- **अमित शाह बोले—'सहकार से समृद्धि' के जरिए पशुपालकों को बाजार, उचित मूल्य और वैल्यू एडिशन का लाभ**

भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में डेयरी सहकारिता के विस्तार और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित गोपालक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सहकारी डेयरी व्यवस्था पशुपालकों को संगठित बाजार, उचित मूल्य और दूध के मूल्यवर्धन का सीधा लाभ दिलाने का प्रभावी माध्यम है।

श्वेत क्रांति 2.0 : 75 हजार नई डेयरियों का लक्ष्य

शाह ने बताया कि श्वेत क्रांति 2.0 के तहत देशभर में 75 हजार नई सहकारी डेयरियां स्थापित करने तथा 46 हजार मौजूदा डेयरियों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में भी सहकारी डेयरी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पशुपालक सहकारी व्यवस्था से जुड़ सकें।



देश का दूध उत्पादन 14.60 से बढ़कर 24.80 करोड़ टन

केंद्रीय मंत्री के अनुसार देश में दूध उत्पादन वर्ष 2014-15 में लगभग 14.60 करोड़ टन था, जो बढ़कर करीब 24.80 करोड़ टन हो गया है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 307 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 485 ग्राम प्रतिदिन हुई है। भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है।

दूध से उत्पाद, बढ़ेगी पशुपालकों की कमाई

शाह ने कहा कि पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए केवल दूध उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। दूध से आइसक्रीम, मक्खन, घी, चीज और मावा जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए आधुनिक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और विपणन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने नस्ल सुधार, टीकाकरण, चारा प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स-सॉर्टेड सीमन जैसी तकनीकों को पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन बताया।

महिलाओं की आय और भागीदारी पर जोर

अमित शाह ने कहा कि डेयरी सहकारिता महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। डेयरी से होने वाली आय सीधे महिलाओं तक पहुंचने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है। कार्यक्रम में पशुपालकों को बोनस, लाभांश और सहायता राशि वितरित की गई तथा महिला पशुपालकों सहित अन्य पशुपालकों को सम्मानित किया गया।

सहकारिता से उत्पादन से बाजार तक जुड़ेंगे पशुपालक: शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के तहत सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, डेयरी और महिला सशक्तीकरण से जोड़ा जा रहा है। सहकारी डेयरी मॉडल के माध्यम से पशुपालकों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और बाजार तक एक संगठित व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में 255 करोड़ का डेयरी प्लांट

सम्मेलन के दौरान उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट का डिजिटल माध्यम से भूमिपूजन किया गया।

इसके साथ ही—

- भोपाल: 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का लोकार्पण।
- भोपाल: 12.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाला का लोकार्पण।
- शिवपुरी: मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण।

1,001 से 5,000 करोड़ रुपये जमा श्रेणी में हासिल किया दूसरा स्थान

मॉडल को-ऑपरेटिव बैंक ने जीता 'बेस्ट बैंक अवॉर्ड'



मुंबई। मुंबई स्थित मॉडल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 1,001 से 5,000 करोड़ रुपये तक जमा वाले बैंकों की श्रेणी में 'बेस्ट बैंक अवॉर्ड प्रतियोगिता' में दूसरा पुरस्कार हासिल किया है। पुरस्कार का आयोजन द बृहन्मुंबई नागरी सहकारी बैंक्स एसोसिएशन लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया गया।

एसोसिएशन की 48वीं वार्षिक आमसभा के अवसर पर 30 सितंबर 2026 को मुंबई के कुर्ला स्थित बुंट्स संघ में आयोजित समारोह में बैंक को यह सम्मान प्रदान किया गया। एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाबराव गणपतराव जगताप और वाइस चेयरमैन दिलीप जगन्नाथ चव्हाण ने बैंक प्रतिनिधियों को पुरस्कार प्रदान किया। बैंक की ओर से संस्थापक निदेशक विसेंट मैथियास, निदेशक एडवोकेट पायस वास, प्रोफेशनल डायरेक्टर सीए पॉल नाज़रेथ, निदेशक हिलेरी मेंडोंका, जनरल मैनेजर एवं सीईओ हेनरी बी. क्राड्रोस तथा एडिशनल जनरल मैनेजर ज़ेनॉन डी'करूज़ ने पुरस्कार ग्रहण किया। यह सम्मान बैंक की बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय प्रदर्शन और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने वाला महत्वपूर्ण सम्मान है।

शरद सहकारी बैंक का कारोबार मजबूत जमा 2,024 करोड़ रुपए के पार



पुणे। शरद सहकारी बैंक लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में वित्तीय मजबूती का प्रदर्शन करते हुए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 मार्च 2026 तक बैंक की कुल जमा राशि 8.50 प्रतिशत बढ़कर 2,024.69 करोड़ रुपये हो गई, जबकि अग्रिम 9.57 प्रतिशत बढ़कर 1,378.53 करोड़ रुपये पहुंच गया।

जमा में 8.50% और अग्रिम में 9.57% वृद्धि; सकल लाभ बढ़कर 41.50 करोड़ रुपये

बैंक का सकल लाभ 35.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 41.50 करोड़ रुपये हो गया। वहीं बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान 10.18 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। बैंक ने सदस्यों को 10 प्रतिशत लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है।

नेटवर्थ 142.22 करोड़ रुपये

बैंक की चुकता शेयर पूंजी 51.39 करोड़ रुपये और नेटवर्थ 142.22 करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष के अंत में बैंक का सीआरएआर 13.83 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो बैंक की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति को दर्शाता है।

ग्राहक-केंद्रित सेवाओं पर जोर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्यों को संबोधित करते हुए बैंक के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने कहा कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए ग्राहक-केंद्रित सेवाओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बैंक की प्रगति में निदेशक मंडल, प्रबंधन, कर्मचारियों, सदस्यों, जमाकर्ताओं और ग्राहकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। जमा, अग्रिम और लाभ–तीनों प्रमुख वित्तीय संकेतकों में वृद्धि के साथ शरद सहकारी बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखा है।

समीर बनर्जी निर्विरोध बने सारस्वत बैंक के चेयरमैन

किशोर मसूरकर उपाध्यक्ष निर्वाचित; बैंक का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये के पार



मुंबई। देश के प्रमुख शहरी सहकारी बैंकों में शामिल सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को नया नेतृत्व मिला है। समीर कुमार बनर्जी को बैंक का चेयरमैन तथा किशोर गुरुदास मसूरकर को उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। दोनों के निर्वाचन को सहकारिता मंत्रालय के अधीन सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है।

समीर कुमार बनर्जी ने निवर्तमान चेयरमैन गौतम ठाकुर का स्थान लिया है। ठाकुर के कार्यकाल में बैंक के कुल कारोबार में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान बैंक ने कारोबार विस्तार और संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की।

19 सदस्यीय बोर्ड भी निर्विरोध

सारस्वत बैंक का 19 सदस्यीय निदेशक मंडल भी निर्विरोध चुना गया था। बैंक का कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे में नए नेतृत्व के सामने बैंक के विस्तार, डिजिटल बैंकिंग, सहकारी सदस्य सेवाओं और वित्तीय मजबूती को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।

करीब पांच दशक से बैंक से जुड़े हैं बनर्जी

नवनिर्वाचित चेयरमैन समीर कुमार बनर्जी करीब पांच दशकों से सारस्वत बैंक से जुड़े हैं। वे इससे पहले बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और 2002 से 2017 तक प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बनर्जी ने बीएससी (ऑनर्स) के साथ डीबीएम, एलएल.एम. और एफआई.आई. बी.एफ की योग्यता हासिल की है। बैंक में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रशासन, ऑडिट, विधि, ट्रेजरी, परिचालन, लेखा, विपणन और परियोजना प्रबंधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारियां संभाली हैं। वर्तमान में वे बैंक के निदेशक मंडल की कार्यकारी एवं मानव संसाधन समिति के चेयरमैन तथा क्रेडिट समिति के सदस्य हैं।

मसूरकर बने उपाध्यक्ष

किशोर गुरुदास मसूरकर को बैंक का उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बायोकैमिस्ट्री में एमएससी तथा प्रशासनिक प्रबंधन में डिप्लोमा किया है। वे अनुसंधान आधारित फार्मास्युटिकल समूह एंटोड इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं।

गोदावरी अर्बन का कारोबार 5,561 करोड़ रुपये पहुंचा

29.32 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ, सदस्यों को 7 प्रतिशत लाभांश की घोषणा

महाराष्ट्र। गोदावरी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने अपनी 13वीं वार्षिक आमसभा में वित्तीय वर्ष की उपलब्धियां साझा करते हुए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया। संस्था का कुल कारोबार बढ़कर 5,561 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि 29.32 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर सदस्यों के लिए 7 प्रतिशत लाभांश घोषित किया गया।



वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रबंध निदेशक धनंजय तांबेकर ने बताया कि संस्था की कुल जमा 3,079 करोड़ रुपये और ऋण वितरण 2,481 करोड़ रुपये रहा। दोनों को मिलाकर संस्था का कुल कारोबार 5,561 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा।

वित्तीय अनुशासन से मजबूत हुई संस्था

अध्यक्ष राजश्री पाटील ने संस्था की प्रगति का श्रेय वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रबंधन और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं को दिया। उन्होंने कहा कि संस्था सहकारी मूल्यों के अनुरूप सदस्यों और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि संस्थापक अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य हेमंत पाटील के मार्गदर्शन में गोदावरी अर्बन सहकारिता क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।

मुख्य आंकड़े:

- कुल कारोबार: 5,561 करोड़
- कुल जमा: 3,079 करोड़
- ऋण वितरण: 2,481 करोड़
- शुद्ध लाभ: 29.32 करोड़
- सदस्यों को लाभांश: 7 प्रतिशत

जब बाहर से आई एक नज़र ने सिखाया भरोसे का पाठ

विशेष श्रृंखला भाग-5 : अंकेक्षण — पारदर्शिता की परीक्षा

पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि कैसे सदस्यों की छोटी-छोटी अंशपूँजी मिलकर समिति की बड़ी आर्थिक ताकत बनी। पर एक सवाल अब भी बाकी था — यह पूँजी सही ढंग से खर्च हो रही है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसी सवाल का जवाब देने एक दिन समिति के दफ्तर में एक अजनबी चेहरा पहुँचा — हाथ में रजिस्टर, आँखों में बारीकी से जाँचने की आदत। यह थे अंकेक्षक (ऑडिटर), और उनकी यह यात्रा ही आज की कहानी है।

जाँच से घबराना क्यों?

अंकेक्षक के आने की खबर सुनते ही समिति के दफ्तर में हल्की-सी हलचल मच गई। कुछ सदस्यों के मन में सवाल था – 'क्या कोई गलती पकड़ी जाएगी?' कोषाध्यक्ष मुस्कुराए और बोले, 'अंकेक्षण गलती पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह भरोसा दिलाने के लिए होता है कि सब कुछ सही चल रहा है।' यही सोच अंकेक्षण को डर की नहीं, बल्कि आश्वासन की प्रक्रिया बनाती है। अंकेक्षण दरअसल एक स्वतंत्र, निष्पक्ष नज़र है जो समिति के हिसाब-किताब को बाहर से परखती है। यह न तो प्रबंध समिति के भरोसे पर निर्भर करता है, न ही सदस्यों की धारणा पर– यह तथ्यों और दस्तावेज़ों की सीधी जाँच है।

रजिस्टर-दर-रजिस्टर, बारीकी से जाँच

अंकेक्षक ने दिन भर एक-एक रजिस्टर खंगाला – सदस्यता रजिस्टर, रोकड़ बही, बैठक कार्यवाही, खरीद के बिल। हर एक रसीद का मिलान खाते से किया गया। शाम होते-होते उन्होंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी सुनाई – ज़्यादातर हिसाब सही था, पर एक जगह मामूली विसंगति मिली, जिसे तुरंत सुधारने की सलाह दी गई। ÷अंकेक्षण में मिली छोटी कमी बड़ी गलती बनने से पहले ही रोक ली जाती है – यही इसका सबसे बड़ा फायदा है।

नई समितियों के लिए सीख

जो समितियाँ साल भर अपने अभिलेख व्यवस्थित रखती हैं, हर लेन-देन का बिल सहेजती हैं और अंकेक्षक के सुझावों को गंभीरता से लागू करती हैं, उनके लिए अंकेक्षण एक सहज, तनाव-मुक्त प्रक्रिया बन जाता है। पारदर्शिता कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज़-रोज़ की आदत है। अगले अंक में हम पढ़ेंगे — निर्वाचन की कहानी, जहाँ समिति का नेतृत्व एक हाथ से दूसरे हाथ में सहजता से बदलता है। तब तक के लिए, सहकार समाचार पढ़ते रहिए।

अंकेक्षक

जो समितियाँ अंकेक्षण को सहयोग की भावना से लेती हैं, वे हर साल थोड़ा और बेहतर होती जाती हैं। जो समितियाँ इसे केवल एक बोझिल औपचारिकता मानती हैं, वहाँ छोटी-छोटी खामियाँ अनदेखी होकर आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती हैं।

दो समितियाँ, दो नतीजे

पड़ोस की एक समिति में अंकेक्षण के दौरान कुछ भुगतान बिना उचित बिल के पाए गए। जब कारण पूछा गया, तो सचिव के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। इस घटना ने सदस्यों का भरोसा हिला दिया, और अगली आमसभा में इसी विषय पर लंबी बहस हुई। इसके उलट, जिस समिति की हमने शुरुआत में बात की, वहाँ अंकेक्षक की छोटी-सी सलाह को समिति ने उसी हफ्ते लागू कर दिया। अगले साल के अंकेक्षण में कोई विसंगति नहीं मिली, और सदस्यों ने खुले मन से समिति के कामकाज पर भरोसा जताया।

अंकेक्षण रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई ही असली पारदर्शिता की पहचान है, केवल रिपोर्ट मिलना नहीं

भरोसे की नींव मज़बूत करने वाला औज़ार

अंकेक्षण केवल गलतियाँ खोजने का ज़रिया नहीं, बल्कि समिति की साख को मज़बूत करने का सबसे भरोसेमंद औज़ार है। जब अंकेक्षण रिपोर्ट साफ आती है, तो यह पूरी सदस्यता के लिए एक तरह का प्रमाणपत्र बन जाती है – कि उनकी मेहनत की कमाई सही हाथों में है। वहीं जब कोई कमी सामने आती है, तो समय रहते उसका समाधान समिति को बड़े संकट से बचा लेता है। इसीलिए अनुभवी सहकारिता कार्यकर्ता अक्सर कहते हैं कि जो समिति अंकेक्षण से नहीं डरती, वही असल में मज़बूत समिति होती है।

- पुरुषोत्तम सोनी, व्याख्याता

प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ





किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

जयपुर। प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ मंगलवार को करधनी शॉपिंग सेंटर, मालवीय नगर, जयपुर में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक के कर-कमलों से किया गया। इस अवसर पर शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में सीईओ, पीएमबीआई डॉ. शांतनु कुमार सहित संबंधित अधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ मरीजों की बढ़ती मांग तथा आमजन को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां एवं सर्जिकल आइटम्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

1200 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, शीघ्र 2000 + तक की जाएंगी

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र पर वर्तमान में 1200 से अधिक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। आमजन की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र ही इनकी संख्या बढ़ाकर 2000 तक किए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही दवाइयां एवं सर्जिकल आइटम्स बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में लगभग 50 से 80 प्रतिशत तक कम दरों पर उपलब्ध हैं। इससे आमजन एवं मरीजों को उपचार के दौरान होने वाले दवा खर्च में राहत मिलेगी। दक ने कहा कि अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र संचालित होने से मरीजों एवं उनके परिजनों को दवाइयों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल से उपलब्ध नहीं हो पाने वाली दवाइयां भी केन्द्र पर किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी।

जेनेरिक दवाइयां निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण

शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा दवाइयां जेनेरिक नाम से ही प्रिस्क्राइब किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि मरीजों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही दवाइयां एवं सर्जिकल आइटम्स गुणवत्ता संबंधी निर्धारित सभी मापदण्डों को पूरा करने के उपरान्त ही बाजार में उपलब्ध कराए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता एवं प्रभाव संबंधित साल्ट वाली ब्राण्डेड दवाइयों के समान ही होता है। डॉ. शर्मा ने बताया कि जेनेरिक दवाइयों की कीमत अपेक्षाकृत कम होने का प्रमुख कारण इनके विपणन एवं ब्राण्डिंग पर होने वाले व्यय तथा आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर देय कमीशन आदि का कम होना है। इससे गुणवत्तापूर्ण दवाइयां आमजन को कम कीमत पर उपलब्ध कराना संभव होता है।

गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं

इस अवसर पर भारत सरकार से पधारे, जन औषधि के सीईओ, पीएमबीआई डॉ. शांतनु कुमार ने कहा कि जेनेरिक दवाइयों का प्रभाव समान साल्ट वाली ब्राण्डेड दवाइयों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयां निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होती हैं। उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाइयों की कम कीमत का अर्थ उनकी गुणवत्ता में कमी नहीं है, बल्कि इनके विपणन, ब्राण्डिंग एवं वितरण से जुड़े खर्चों में कमी के कारण ये दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध हो पाती हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र की सुविधाओं एवं यहां उपलब्ध दवाइयों तथा सर्जिकल आइटम्स की जानकारी भी दी गई।

दुर्ग में एग्रीस्टेक पंजीयन के लिए लगाए गए शिविर

दुर्ग। धान खरीदी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों एवं उनके सह-हिस्सेदारों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टेक पंजीयन होना अनिवार्य है। इस हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध सेवा सहकारी समिति में संचालित कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से एग्रीस्टेक पंजीयन का कार्य अपने आश्रित ग्रामों में शिविर आयोजित कर किया जा रहा है।

जिला दुर्ग में कुल 87 समितियों के आश्रित ग्रामों में 10 सितंबर से शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि 30 सितंबर तक चलेंगे। शिविरों में जिले के सभी तहसील के कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी भी उपस्थित रहकर शासन की महत्वपूर्ण योजना में सहयोग प्रदाय कर रहे है। इस संबंध में पूर्व ही सहकारिता विभाग, अधिकक्षक भू-अभिलेख एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध सेवा सहकारी समितियों के समिति प्रबंधक / प्रभारियों की समीक्षा बैटक जिले के कलेक्टर द्वारा जा चुकि है।

बिना एग्रीस्टेक पंजीयन धान नहीं बिकेगा : कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि, बिना एग्रीस्टेक पंजीयन धान नहीं बिकेगा, सह खातेदारों का भी पंजीयन होना भी आवश्यक है। उन्होने कहा कि इस वर्ष 2026-27 में धान बिक्री के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन एवं सह-खातेदारों का बकेट क्लेम (सहमति सत्यापन) अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक हिस्सेदार के नाम से बकेट आईडी बनती है, जिसे एग्रीस्टेक में पंजीयन कराना आवश्यक है।



बकेट क्लेम सबसे ज्यादा दुर्ग जिले में

प्रदेश में सर्वाधिक दुर्ग जिले का 458957 बकेट क्लेम (सहमति सत्यापन) का पंजीयन किया जाना है, जिसे शिविर के माध्यम से शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लक्ष्य है। समिति प्रबंधक / प्रभारी एवं संबंधित अमले को सभी लंबित बकेट क्लेम का कार्य समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया गया था, जिसकी समीक्षा अनुविभागीय अधिकारियों एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा की जा रही है। शिविर के माध्यम से एग्रीस्टेक में बकेट क्लेम के पंजीयन में निरंतर प्रगति हो रही है।



असम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को दुर्गा पूजा पर 10 हजार रुपये का तोहफा

पहली छमाही में 36.04 करोड़ रुपये का मुनाफा, अध्यक्ष बिश्वजीत फूकन ने कर्मचारियों के योगदान को सराहा

गुवाहाटी। असम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (एपेक्स बैंक) ने दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने प्रत्येक कर्मचारी को 10,000 रुपये का विशेष उपहार देने की घोषणा की है। बैंक ने यह घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 36.04 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज करने के बाद की है।

बैंक के अध्यक्ष बिश्वजीत फूकन ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और निदेशक मंडल को वित्तीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। फूकन के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को समाप्त छह माह की अवधि में बैंक ने 36.04 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया। उन्होंने इस उपलब्धि में अधिकारियों, कर्मचारियों और निदेशक मंडल के योगदान की सराहना की। अध्यक्ष ने कहा कि, दुर्गा पूजा के अवसर पर कर्मचारियों को दिया जा रहा विशेष उपहार उनके मनोबल और उत्साह को बढ़ाने के उद्देश्य से है। उन्होंने बैंक के वित्तीय प्रदर्शन को ÷अभूतपूर्व वित्तीय सफलता÷ बताते हुए पूरी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की।

वित्तीय प्रदर्शन के साथ कर्मचारी हित पर जोर

असम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की यह पहल सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण को भी रेखांकित करती है। बैंक के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा को सहकारिता क्षेत्र में कर्मचारी-हित की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

छोटे किसानों के लिए कृषक उत्पादक संगठन मददगार बनी बड़ाजीं



बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत बस्तर जिला सहकारी संघ मर्यादित जगदलपुर एवं इफ्को के क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर के सहयोग से बस्तर जिले की लौंहडीगुड़ा विकासखंड अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़ाजीं में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया गया । प्रशिक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के जगदलपुर में कार्यरत प्रशिक्षण इकाई द्वारा उपस्थित ग्रामीण कृषक सदस्यों को सहकारिता के अर्थ महत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए लेंपस द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विस्तार से ज्ञान करवाया जाकर कृषक सदस्यों से आवाहन किया गया कि एक चक में खेती करने वाले किसान संगठित होकर कृषक उत्पादक संगठन का गठन करें जिससे किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बड़े बाजार में पहुंचाकर मूल्य वृद्धि संभव हो सके वही खेती के संसाधनों का भी संग्रहण कर बारहमासी खेती संभव कर खेती को मुख्य व्यवसाय बनाया जा सके ।

आईसीए के वैश्विक बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे दिलीप संघानी की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात

हैदराबाद में 'वेलनेस बाय हार्टफुलनेस' कार्यक्रम के दौरान हुई भेंट, भारतीय सहकारिता की वैश्विक पहचान को लेकर बढ़ी उम्मीदें



हैदराबाद। इफ्को के चेयरमैन एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के ग्लोबल बोर्ड में एट-लार्ज निदेशक श्री दिलीप संघानी ने हैदराबाद के निकट कान्हा शांति वनम में आयोजित 'वेलनेस बाय हार्टफुलनेस' कार्यक्रम के दौरान भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण भेंट हुई।

श्री संघानी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुलाकात की जानकारी साझा की। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद ने उन्हें अपनी पुस्तक 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक' भेंट की। श्री संघानी ने उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सरल व्यक्तित्व और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को प्रेरणादायी बताया।

आईसीए के वैश्विक बोर्ड में भारत की भागीदारी

यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) की पनामा में आयोजित महासभा एवं बोर्ड चुनाव में श्री संघानी की भागीदारी के बाद हुई। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वे आईसीए के ग्लोबल बोर्ड में एट-लार्ज निदेशक निर्वाचित हुए हैं। यह जिम्मेदारी उन्हें वैश्विक सहकारी मंच पर भारतीय सहकारी आंदोलन के अनुभवों और उपलब्धियों को साझा करने का अवसर प्रदान करती है।

'सहकार से समृद्धि' को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का अवसर

अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन विश्वभर के सहकारी संगठनों का प्रमुख वैश्विक मंच है। इसके वैश्विक बोर्ड में भारतीय सहकारी नेतृत्व की भागीदारी से भारत की सहकारिता परंपरा, सदस्य-केंद्रित विकास और सहकारी संस्थाओं की भूमिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। भारत में सहकारिता को आर्थिक एवं सामाजिक विकास का प्रभावी माध्यम बनाने के लिए संचालित 'सहकार से समृद्धि' की पहल के संदर्भ में भी वैश्विक अनुभवों का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण है। श्री संघानी की अंतरराष्ट्रीय भूमिका भारतीय सहकारी क्षेत्र के लिए वैश्विक संवाद और सहयोग के नए अवसरों का माध्यम बन सकती है।

'सहकार से समृद्धि' को डिजिटल विस्तार देने की तैयारी, ओएनडीसी के साथ चर्चा

सहकारिता मंत्रालय ने समर्पित डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम विकसित करने पर किया मंथन

डेयरी, कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों को मिलेगा व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का अवसर



नई दिल्ली। देशभर की सहकारी संस्थाओं के उत्पादों को व्यापक उपभोक्ता बाजार तक पहुंचाने और सहकारी

क्षेत्र को डिजिटल वाणिज्य से जोड़ने की दिशा में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने पहल तेज की है। इसी क्रम में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के सहयोग से सहकारी उत्पादों के लिए एक समर्पित डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम विकसित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में 6 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष भूटानी की अध्यक्षता में ओएनडीसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में संयुक्त सचिव श्री रमन कुमार, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रमुख सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सहकारी उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने पर जोर बैठक में ऐसे डिजिटल नेटवर्क के विकास पर चर्चा की गई, जो सहकारी संस्थाओं और उनके उत्पादकों को व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान कर सके। इसके लिए बाजार संपर्क, मूल्य श्रृंखला, डिजिटल भुगतान, लॉजिस्टिक्स तथा तकनीकी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया।प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से डेयरी उत्पादों, कृषि उपज, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, हथकरघा, हस्तशिल्पऔर जैविक उत्पादों सहित विभिन्न सहकारी उत्पादों को स्थानीय बाजारों से आगे राष्ट्रीय स्तर पर पहचानदिलाने की संभावनाएं हैं। ओएनडीसी मॉडल से छोटे सहकारी संगठनों को लाभ की उम्मीद ओएनडीसी का ओपन नेटवर्क मॉडल विक्रेताओं को किसी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सीमित रहने केबजाय विभिन्न खरीदार एप्लिकेशन के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है।इससे छोटे और ग्रामीण सहकारी संगठनों को नए ग्राहकों तक पहुंचने तथा अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

ऋण उप समिति की बैठक में 30 करोड़ का ऋण स्वीकृत



दुर्ग। श्री प्रीतपाल बेलचंदन अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की अध्यक्षता में ऋण उप समिति की बैठक 9 अक्टूबर को सम्पन्न हुई। बैठक में श्री नरेश यदु उपाध्यक्ष, कु.शिवांगी महार, सहायक पंजीयक सहकारिता, श्री सुमन कुमार कोर्राम सहायक संचालक कृषि एवं श्री एस.के.वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बैंक के कार्यक्षेत्र जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा के 33 सहकारी समितियों के 2169 कृषकों के लिए फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पूरक साख सीमा वर्ष 2026-27 से 2028-29 राषि 24.86 करोड़ रु., गन्ना उत्पादन हेतु 8 कृषकों को साख सीमा 13.18 लाख रु., उद्यानिकी फसल टमाटर के अंतर्गत 6 कृषकों को 8.18 लाख, गौपालन हेतु नवीन केसीसी साख सीमा वर्ष 2026-27 के लिए 149 कृषकों को 3.10 करोड़ रु., गौपालन हेतु साख सीमा का नवीनीकरण वर्ष 2026-27 हेतु 55 कृषकों का 1.08 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया है।

इन्हें भी मिलेगा ऋण

मत्स्य पालन हेतु 8 कृषकों को 22.00 लाख, बकरी पालन हेतु 5 कृषकों को 6 लाख रु., कुक्कुट पालन हेतु 2 कृषकों को 6 लाख रु., 13 अमानतदारों को व्यक्तिगत ऋण 51.60 लाख, 1 स्वयं सहायता समूह को 3 लाख रु. मध्यम कालीन नार्मल ऋण अंतर्गत 1 कृषक को 2.14 लाख रु. गोल्डन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत 1 किसान को 5.00 लाख रु. ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार अन्य हितग्राहियों के मांग अनुसार अकृषि ऋण स्वीकृत किया गया।

किसानों के बीच प्रचार-प्रसार का लिया गया निर्णय

बैंक के माध्यम से ऋण नीति अनुसार उप संचालक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य विभाग के विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कृषकों के मध्य करने हेतु अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया ताकि बैंक के माध्यम से इन योजनाओं में अधिकाधिक कृषक लाभान्वित हो। बैठक में सुश्री कुसुम ठाकुर अतिरिक्त मुख्य पर्यवेक्षक एवं श्री एस.पी.वाहने शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।



लैंपस पैक्स की व्यवसाय वृद्धि से सदस्य होंगे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित

सिरिसगुड़ा। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, कृषक सदस्यों को उनके अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने तथा सहकारी संस्थाओं की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोहंडीगुड़ा विकासखंड के लेंपस सिरिसगुड़ा में सदस्य सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा के मार्गदर्शन में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कृषक सदस्यों को सहकारिता के मूल सिद्धांतों, लेंपस-पैक्स की भूमिका, व्यवसाय विस्तार, पशुपालन तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम का आयोजन बस्तर जिला सहकारी संघ मर्यादित, जगदलपुर एवं इफ्को के क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के प्रति सदस्यों की समझ विकसित करना, उन्हें संस्था की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना तथा सहकारिता के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की संभावनाओं से परिचित कराना रहा।

सहकारी संस्थाओं की मजबूती से सदस्यों को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभः प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, रायपुर के प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे ने लेंपस सभागृह में उपस्थित कृषक सदस्यों को सहकारिता के अर्थ, महत्व, उद्देश्य एवं प्रमुख सिद्धांतों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सदस्य आपसी सहयोग, सहभागिता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

उन्होंने लेंपस संस्था की कार्यप्रणाली और कृषक सदस्यों के साथ उसके संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लेंपस-पैक्स के व्यवसाय में वृद्धि होने से कृषक सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने के अवसर प्राप्त होंगे। सहकारी संस्थाओं का व्यवसाय जितना अधिक मजबूत होगा, किसानों को विभिन्न सहकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ेंगी।

श्री पांडे ने कहा कि सहकारी संस्था केवल कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और किसानों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके लिए आवश्यक है कि सदस्य संस्था के कार्यों को समझें, बैठकों में भाग लें, उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग करें और संस्था के व्यवसाय विस्तार में अपना योगदान दें।उन्होंने कृषक सदस्यों को सहकारिता के मूल उद्देश्यों से जोड़ते हुए संस्था के विकास को सदस्यों की आर्थिक प्रगति के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता पर बल दिया।

गोपालन एवं बकरी पालन से बढ़ सकती है किसानों की आयः बस्तर जिला सहकारी संघ मर्यादित, जगदलपुर के प्रबंधक श्री सी.के. द्विवेदी ने प्रशिक्षण के दौरान कृषक सदस्यों को कृषि के साथ-साथ पशुपालन गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से गोपालन एवं बकरी पालन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इन गतिविधियों को अपनाकर किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

सहकारी मॉडल से एग्रीबिजनेस को बढ़ावा वामनिकॉम में 52 सैन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण

'इनोवेशन एंड एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट' कार्यक्रम में सहकारिता, सामूहिक उद्यम और मूल्य-श्रृंखला पर जोर



पुणे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमिता के साथ सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने की दिशा में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वामनिकॉम), पुणे ने पहल की है। रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के सहयोग से संस्थान में सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए 'इनोवेशन एंड एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 28 सितंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के 52 अधिकारी भाग ले रहे हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमिता, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के साथ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक व्यवसाय की संभावनाओं से परिचित कराना है।

छोटे उद्यमों को सहकारिता से मिल सकता है विस्तार

वामनिकॉम के निदेशक डॉ. सुवा कांता मोहंती ने कहा कि उचित योजना और प्रबंधन के साथ छोटे उद्यम स्थायी आय का आधार बन सकते हैं। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास, नवाचार और सहकारी मॉडल छोटे-छोटे उद्यमों को व्यापक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने सहकारी संस्थाओं के माध्यम से संसाधनों के साझा उपयोग, बाजार तक पहुंच और सामूहिक क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर भी जोर दिया।

कृषि मूल्य-श्रृंखला की समझ पर जोर

पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. अमित बोरकर ने कृषि व्यवसाय में मूल्य-श्रृंखला प्रबंधन की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को व्यावसायिक अवसरों की पहचान, परियोजना तैयार करने, वित्तीय प्रबंधन, विपणन और उद्यम विकास के साथ कृषि उत्पादों की प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं बाजार से जुड़ाव की जानकारी दी जा रही है। सहकारी मॉडल के संदर्भ में प्रतिभागियों को यह समझाने पर जोर दिया जा रहा है कि उत्पादक समूहों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों एवं उद्यमियों को बाजार से जोड़कर छोटे व्यवसायों को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है।

'सहकार से उद्यमिता' की दिशा में प्रशिक्षण

कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय के दक्षिण क्षेत्र के अपर महानिदेशक ब्रिगेडियर रंजन केरन ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिकारियों के भविष्य के व्यावसायिक एवं उद्यमशील अवसरों में उपयोग करने पर जोर दिया। वामनिकॉम के कृषि-व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी कार्यक्रम से जोड़ा गया है। भागीरथी एम. और सिद्धार्थ सिंह ने उद्घाटन सत्र का संचालन किया, जिससे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव मिला। वामनिकॉम के रजिस्ट्रार डॉ. सुदाम अडलींगे ने आभार व्यक्त किया। सहायक प्रोफेसर एवं सह-समन्वयक डॉ. अरविंद दर्शना सहित संस्थान के अन्य संकाय सदस्य कार्यक्रम से जुड़े हैं। कृषि-व्यवसाय, नवाचार और सहकारी मॉडल को एक साथ जोड़ने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए नए आजीविका अवसरों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी उद्यमों से जुड़ने की संभावनाएं भी खोलता है।



छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ रायपुर के तत्वावधान में 7 अक्टूबर को आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। श्री सौरभ शर्मा के मार्गदर्शन में बस्तर जिला के आंगनबाड़ी केंद्र परपा में महिलाओं का सहकारी प्रशिक्षण सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी विवेकानंद झा द्वारा दिया गया।

महिलाओं को सहकारिता का महत्व, सहकारिता से समृद्धि लाने के विषय में तथा छोटे एवं लघु उद्योग सहकारिता के माध्यम से स्थापना तथा नए सहकारी समिति के पंजीयन के विधि, सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य विभाग के असीम मसीह सीएचओ तथा श्रीमती सुशीला तिवारी एएनएम के द्वारा पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शिशु एवं माता को कुपोषण से बचाव बच्चों एवं माता को पौष्टिक भोजन देने के बारे में बताया गया। गर्भवती माता तथा छोटे बच्चों को दवाई वितरण किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सुदन मौर्य का विशेष योगदान रहा।

सरगीपाल में महिलाओं को दिया गया सहकारी प्रशिक्षण



बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ रायपुर के तत्वावधान में 12 अक्टूबर को सरगीपाल में महिलाओं का सहकारी प्रशिक्षण सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी विवेकानंद झी द्वारा दिया गया।

प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरव शर्मा जी के मार्गदर्शन पर आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सरगीपाल में महिलाओं का सहकारी प्रशिक्षण सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी विवेकानंद झा द्वारा दिया गया। महिलाओं को सहकारिता का महत्व, आज के परिवेश में सहकारिता की भूमिका, सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, आर्थिक उन्नति ,बचत सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाना, सहकारिता के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना, लघु व छोटे उद्योग की स्थापना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सुदन मौर्य संपर्क साधक का प्रयास रहा ।

सहकार भारती ने क्रेडिट सहकारी समितियों को टेक्नोलॉजी और नवाचार से जोड़ने की दिशा में बढ़ाया कदम

सहकारिता और स्टार्टअप के बीच नई साझेदारी की पहल

अहमदाबाद। सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने की दिशा में सहकार भारती की गुजरात इकाई ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत अहमदाबाद स्थित आईहब में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं के डिजिटल रूपांतरण, नवाचार, पेशेवर प्रबंधन और स्टार्टअप के साथ संभावित सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई।

तकनीक से मजबूत होंगी सहकारी संस्थाएं: कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि स्टार्टअप आधुनिक तकनीक आधारित समाधान उपलब्ध कराकर क्रेडिट सहकारी समितियों की कार्यकुशलता, सेवा गुणवत्ता और डिजिटल क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। डिजिटल सेवाओं, डेटा आधारित निर्णय, सदस्य सुविधा और नई तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से सहकारी संस्थाएं बदलती जरूरतों के अनुरूप अपनी सेवाओं को विकसित कर सकती हैं। वहीं, सहकारी क्षेत्र का व्यापक सदस्य आधार और मजबूत जमीनी नेटवर्क स्टार्टअप के लिए नए तकनीकी समाधानों के परीक्षण, स्थानीय स्तर पर उपयोग और बड़े पैमाने पर विस्तार का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

'सहकार से नवाचार' पर जोर

आईहब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरेन महांता सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। सहकार भारती गुजरात की प्रदेश मंत्री जलपा जैन ने कहा कि सहकारिता के पास विश्वास और



व्यापक जमीनी संपर्क है, जबकि स्टार्टअप के पास तकनीक, नवाचार और नए व्यावसायिक समाधान। दोनों की क्षमताओं को जोड़कर सहकारी क्षेत्र के लिए नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी जीवनभाई गोले तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरेशभाई बोरिसागर भी उपस्थित रहे। समापन सत्र में एनसीयूआई के निदेशक नकुल कांडू तथा अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) यूथ के अध्यक्ष हर्ष सांघानी ने भाग लिया। इस दौरान 'सहकार से नवाचार' की अवधारणा के तहत सहकारी संस्थाओं और नवोन्मेषकों के बीच मजबूत संस्थागत संबंध विकसित करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रशिक्षण से आगे, साझेदारी की दिशा में पहल

कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पारंपरिक प्रशिक्षण तक सीमित न रहकर सहकारी संस्थाओं और उभरते उद्यमियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना था। इसके माध्यम से दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को समझते हुए व्यावहारिक सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर दिया गया। यह पहल सहकारी संस्थाओं को तकनीक, नवाचार और आधुनिक प्रबंधन से जोड़कर उन्हें अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और सदस्य-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आई है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की 25 वीं वार्षिक आमसभा संपन्न



किसानों की सेवा, पारदर्शिता और तकनीक बनेगी मार्कफेड की नई कार्यदिशा

मार्कफेड की 25वीं वार्षिक आमसभा में धान उपार्जन से लेकर खाद-उर्वरक और भंडारण व्यवस्था की समीक्षा

रायपुर। किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और सहकारी विपणन व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) की 25वीं वार्षिक आमसभा न्यू सर्किट हाउस, रायपुर में संपन्न हुई। आमसभा में वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ आगामी खरीफ वर्ष में धान उपार्जन, खाद एवं उर्वरक वितरण, भंडारण, पशु आहार व्यवसाय तथा डिजिटल निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से मंथन किया गया।

आमसभा की अध्यक्षता मार्कफेड के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने की। बैठक में प्रबंध संचालक श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, अपर प्रबंध संचालक सुश्री भारती चंद्राकर, वित्तीय नियंत्रक मो. इमरान खान सहित संचालक मंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

धान उपार्जन व्यवस्था में तकनीक पर फोकस

आगामी खरीफवर्ष 2026-27 के धान उपार्जन को लेकर प्रस्तावित लक्ष्य और तैयारियों पर चर्चा हुई। आमसभा में उपार्जन प्रक्रिया की निगरानी को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सहित डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सदस्यों ने खाद एवं उर्वरक वितरण, भंडारण क्षमता, धान के निराकरण तथा पशु आहार व्यवसाय सहित मार्कफेड की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के व्यय बजट और कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

'सहकार से समृद्धि' को बनाया जाएगा आधार

मार्कफेड अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' की भावना के अनुरूप मार्कफेड किसानों और सहकारी संस्थाओं के हित में निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ सहकारी विपणन व्यवस्था में आधुनिक तकनीक को अपनाना जरूरी है। किसानों को समय पर बेहतर सेवाएं मिले, व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़े और सहकारी संस्थाएं अधिक सक्षम बनें, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

आमसभा के सफल आयोजन में अपर प्रबंध संचालक सुश्री भारती चंद्राकर सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में सुश्री भारती चंद्राकर ने उपस्थित सदस्यों, पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सहकारिता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण यह आमसभा किसानों को केंद्र में रखकर मार्कफेड की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और परिणाममुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आई।

प्रशासन की पहल से कांदानार की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान

मनरेगा-डीएमएफटी के अभिसरण से गांव में बना उचित मूल्य दुकान भवन, 10 किमी की दूरी से ग्रामीणों को मिली मुक्ति



रायपुर। बस्तर के सुदूर वनांचल क्षेत्र कांदानार में जिला प्रशासन की पहल ने वर्षों पुरानी ग्रामीण समस्या का स्थायी समाधान कर दिया है। दरभा विकासखंड की ग्राम पंचायत कांदानार में मनरेगा एवं जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफटी) की योजनाओं के प्रभावी अभिसरण से उचित मूल्य दुकान का पक्का भवन तैयार किया गया है। अब ग्रामीणों को राशन लेने के लिए 9 से 10 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

समस्या को पहचाना, संसाधनों का अभिसरण कर निकाला समाधान

कांदानार में उचित मूल्य दुकान के लिए भवन नहीं होने के कारण ग्रामीणों को दूर जाकर राशन लेना पड़ता था। दुर्गम वनांचल क्षेत्र में लंबी दूरी तय करने से ग्रामीणों का समय और आवागमन पर होने वाला खर्च बढ़ रहा था। मजदूरों को कई बार राशन लेने के लिए काम तक छोड़ना पड़ता था।

संसाधनों के समन्वित उपयोग का निर्णय

ग्रामीणों की इस समस्या को स्थानीय स्तर पर चिन्हित कर जिला प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों के समन्वित उपयोग का निर्णय लिया। मनरेगा और डीएमएफटी मद को अभिसरण में लेकर गांव में ही उचित मूल्य दुकान भवन निर्माण की कार्ययोजना तैयार की गई। ग्राम पंचायत कांदानार को कार्य एजेंसी बनाते हुए भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। उल्लेखनीय है कि निर्धारित राशि से कम, लगभग 9.70 लाख रुपये की लागत में भवन का निर्माण पूर्ण किया गया। इससे प्रशासन की योजनाबद्ध कार्यप्रणाली और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग का उदाहरण सामने आया है।

एक परियोजना, दोहरा लाभ- अधोसंरचना भी, रोजगार भी

प्रशासन की इस पहल में डीएमएफटी मद से आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों की व्यवस्था की गई, जबकि मनरेगा के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस तरह एक ही परियोजना के माध्यम से स्थायी ग्रामीण अधोसंरचना का निर्माण और स्थानीय रोजगार सृजन, दोनों उद्देश्यों को साधा गया। गांव में राशन, ग्रामीणों के समय और खर्च की बचतः नवनिर्मित उचित मूल्य दुकान से अब कांदानार के ग्रामीणों को गांव में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। करीब 10 किलोमीटर की आवाजाही से राहत मिलने के कारण ग्रामीणों के समय, श्रम और परिवहन खर्च की बचत हो रही है। कृषि एवं मजदूरी से जुड़े कार्य भी अब राशन लेने के कारण प्रभावित नहीं होंगे।

बस्तर बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया सहकारी बैंक परिवार

मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.22 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई

रायपुर। बस्तर जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सहकारिता क्षेत्र ने संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों एवं जगदलपुर के बंगाली समाज मैत्री संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 2 लाख 22 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिवार के अधिकारी-कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 2 लाख 1 हजार रुपये एकत्रित कर बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए योगदान दिया।



बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप एवं उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास मिश्रा ने सहायता राशि का चेक बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा को सौंपा। इस अवसर पर बैंक के सीईओ श्री के.एस. ध्रुव, अतिरिक्त सीईओ श्री एस.ए. रजा, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री आर.के. सूर्यवंशी, सचिव श्री आशीष बराल सहित बैंक के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बंगाली समाज मैत्री संघ ने भी बढ़ाए हाथ

इसी क्रम में जगदलपुर के बंगाली समाज मैत्री संघ ने भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 21 हजार रुपये का योगदान दिया। संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सहायता राशि का चेक कलेक्टर श्री आकाश



छिकारा को सौंपा। इस अवसर पर मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री दीपक घोष, महासचिव श्री सुनील साहा, कोषाध्यक्ष श्री देवाशीष चौधरी, संयुक्त सचिव श्री देवव्रत बराल एवं वरिष्ठ सदस्य श्री अशोक रंजन मुखर्जी उपस्थित थे।

नेफस्कॉब चुनाव में छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी



5 नवंबर को 21 संचालक मंडल पदों के लिए मतदान, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अस्थायी मतदाता सूची में शामिल

रायपुर। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (नेफस्कॉब) के आगामी संचालक मंडल चुनाव में छत्तीसगढ़ की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। चुनाव के लिए जारी अस्थायी मतदाता सूची में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को देश के 25 पात्र राज्य सहकारी बैंकों के साथ शामिल किया गया है। नेफस्कॉब के 21 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए मतदान 5 नवंबर को होगा।

नेफस्कॉब के चुनाव में छत्तीसगढ़ की भागीदारी राज्य के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। नेफस्कॉब देश के राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधि संगठन है, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विषयों को राष्ट्रीय मंच पर रखने में भूमिका निभाता है।

25 राज्य सहकारी बैंक अस्थायी सूची में

अस्थायी मतदाता सूची में छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित कुल 25 राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंक अस्थायी सूची में शामिल नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन बैंकों के मामलों में निर्धारित पात्रता एवं प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से संबंधित विषय सामने आए हैं।

5 नवंबर को मतदान

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना की जाएगी और चुनाव परिणाम 13 नवंबर या उससे पहले घोषित किया जाना है। नवनिर्वाचित संचालक मंडल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव करेगा। पदाधिकारी चुनाव की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी और 17 नवंबर को मतदान होगा। इसका परिणाम 21 नवंबर या उससे पहले घोषित किया जाएगा। नेफस्कॉब के पिछले संचालक मंडल का कार्यकाल 28 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ समेत राज्य सहकारी बैंकों की भागीदारी से फेडरेशन के नए संचालक मंडल का गठन होगा।

16 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची

अस्थायी मतदाता सूची पर 5 से 9 अक्टूबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। आपत्तियों की जांच 12 से 16 अक्टूबर तक होगी और 16 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। संचालक मंडल के 21 पदों के लिए 21 से 28 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 29 अक्टूबर को तथा नाम वापसी 30 अक्टूबर को होगी। इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

दुग्ध समितियों के विस्तार एवं किसान हित को लेकर समीक्षा बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (CGCDF) द्वारा NPDD 2026-27 के अंतर्गत नवीन दुग्ध समितियों के गठन एवं समिति पंजीयन की प्रगति को लेकर रायपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में CGCDF के प्रबंध संचालक डॉ. एम. जयकृष्ण, डिप्टी एमडी डॉ. सैकत सामंत, प्रोजेक्ट हेड के.सी. बेहरा एवं क्षेत्र संचालन शाखा प्रमुख के.बी. प्रताप सर सहित क्षेत्र संचालन शाखा के छत्तीसगढ़ के समस्त मार्ग प्रवेक्षक (AVEO) उपस्थित रहे।

बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा, कार्ययोजना पर विचार-विमर्श

नवीन दुग्ध समितियों का गठन एवं पंजीयनः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर किसानों को सहकारी दुग्ध व्यवस्था से जोड़ने पर जोर।

दुग्ध संकलन में वृद्धिः अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित कर प्रदेश में दुग्ध संकलन को बढ़ाने की दिशा में कार्य।

AMCS **की स्थापनाः** सभी दुग्ध समितियों में ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (AMCS) स्थापित करने पर विशेष चर्चा, ताकि दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता का व्यवस्थित डेटा उपलब्ध हो सके।



समयबद्ध भुगतान में सहयोगः दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता से संबंधित डिजिटल डेटा के आधार पर किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान को अधिक सुगम एवं समयबद्ध बनाने का प्रयास। किसानों को आधुनिक सुविधाएंः दुग्ध उत्पादक किसानों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में सहयोग देने के लिए उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराने पर चर्चा।

चाप कटर एवं मिनरल मिक्सरः समितियों से जुड़े किसानों को सब्सिडी के माध्यम से चाप कटर एवं कैटल फीड/मिनरल मिक्सर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विचार। नए प्लांट की स्थापनाः गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए नए कैटल फीड एवं मिनरल मिक्सर प्लांट की स्थापना की संभावनाओं पर चर्चा।

'देवभोग' ब्रांड का विस्तारः 'देवभोग' उत्पादों की पहुंच छत्तीसगढ़ के साथ देश के विभिन्न हिस्सों तक बढ़ाने की दिशा में संभावित योजनाओं पर विचार। ग्रामीण दुग्ध व्यवसाय को मजबूतीः दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर दुग्ध व्यवसाय को संगठित एवं मजबूत बनाने पर जोर।

किसान भागीदारीः अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारिता से जोड़कर उन्हें बेहतर बाजार एवं दुग्ध व्यवसाय से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास। प्रमुख उद्देश्यः किसानों की भागीदारी बढ़ाना, दुग्ध संकलन व्यवस्था को आधुनिक बनाना, भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहयोग करना तथा सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों के लिए बेहतर अवसर तैयार करना। NPDD 2026-27 योजना के अंतर्गत इन पहलों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दुग्ध सहकारिता के विस्तार और दुग्ध उत्पादक किसानों से जुड़े अवसरों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

भारत टैक्सी ने उत्तर प्रदेश में किया विस्तार, पांच शहर जुड़े

लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में एक साथ शुरू हुई सेवाएं

नई दिल्ली/लखनऊ। सहकारी परिवहन पहल भारत टैक्सी, जो 'चालक ही मालिक है' के सिद्धांत पर आधारित है, ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में औपचारिक रूप से अपनी सेवाओं का विस्तार किया। इसके तहत लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में एक साथ सेवाएं शुरू की गई।

उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल सहकारी आंदोलन के नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य ड्राइवरों अथवा सारथियों को केवल सेवा प्रदाता के रूप में देखने के बजाय उन्हें स्वामित्व एवं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देकर वास्तविक हितधारक बनाना है।

छह माह में 10 लाख से अधिक सारथी भारत टैक्सी से जुड़े

मोहोल ने बताया कि, फरवरी 2026 में लॉन्च होने के छह माह के भीतर ही 10 लाख से अधिक सारथी भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं, जबकि प्रतिदिन लगभग 2 लाख राइड पूरी हो रही हैं। लगभग 40 लाख यात्री भी इस सेवा से जुड़ चुके हैं। इस अवधि में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे सारथियों के खातों में जमा की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के पांच शहरों के जुड़ने के बाद लगभग 40,000 सारथियों के भारत टैक्सी से पंजीकृत होकर सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है। भारत टैक्सी पहले से ही दिल्ली, गुजरात, मुंबई, जयपुर और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में संचालित हो रही है।



70 हजार से अधिक क्वष्टस् के कंप्यूटरीकरण पर जोर

सहकारिता राज्यमंत्री ने लगभग 70,000 पैक्स (क्वष्टस्) के कंप्यूटरीकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इसकी अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये है। संशोधित मॉडल उपनियमों के अंतर्गत क्वष्टस् को 25 से अधिक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इनमें खाद्यान्न भंडारण, बीमा, जैविक उत्पाद, स्वदेशी बीज, सामान्य सेवा केंद्र, जन औषधि केंद्र तथा ईंधन वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में एम-पैक्स सदस्यता अभियान के माध्यम से लगभग 17.5 लाख किसानों सहित 34 लाख से अधिक नए सहकारी सदस्य पंजीकृत किए गए हैं। लगभग 8,300 क्वष्टस् के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। अप्रैल 2026 से अब तक 1,200 से अधिक नई एम-पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन एवं अन्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल विस्तार

कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' पोर्टल, उर्वरक सेतु मोबाइल एप्लीकेशन तथा उत्तर प्रदेश सहकारी डेटाबेस केंद्र मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ मेट्रो रेल एवं लखनऊ पुलिस ने भारत टैक्सी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात पर विशेष जोर

मंत्री ने बीज, जैविक उत्पादों और निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं के गठन का भी उल्लेख किया। इनके माध्यम से लगभग 70,000 समितियां जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य दूध उत्पादन क्षमता को लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ाना है। साथ ही, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

पैदा होंगे नए अवसर

मोहोल ने कहा कि, भारत टैक्सी के माध्यम से परिवहन क्षेत्र में सहकारी भागीदारी का विस्तार किसानों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर प्रदेश में भारत टैक्सी के विस्तार के साथ सदस्यता अभियान, क्वष्टस् कंप्यूटरीकरण तथा सहकारी परिवहन मॉडल को नए क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।

मोहोल ने कहा कि जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद देश में सहकारी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनसे लगभग 32 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं तथा सहकारी क्षेत्र लगभग 30 क्षेत्रों में कार्यरत है।

सहकारिता गरीब महिलाओं को बना सकती है मालिक : नंदिनी आजाद

ऋण से आगे बढ़कर परिसंपत्ति स्वामित्व, उद्यमिता और नेतृत्व तक पहुंचाना जरूरी

चेन्नई। गरीब महिलाओं को केवल ऋण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। सहकारिता के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम, परिसंपत्तियों की स्वामिनी, उद्यमी और निर्णयकर्ता बनाया जा सकता है। यह विचार नंदिनी आजाद ने आईआईटी मद्रास में आयोजित आर्टिब्यूट 2026 के थीम लॉन्च "Shades of Her – Tribute to Women" को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि तकनीकी और आर्थिक प्रगति तभी सार्थक होगी, जब महिलाओं को आर्थिक अवसरों के साथ निर्णय लेने की क्षमता और स्वायत्तता भी प्राप्त हो। विज्ञान, नवाचार और महिला सशक्तिकरण को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने आईआईटी मद्रास एवं शास्त्र टीम की सराहना की।



6 लाख से अधिक महिलाएं सहकारी नेटवर्क से जुड़ीं

आजाद ने बताया कि वर्किंग वुमेन्स फोरम ने 1978 तथा इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर विमेन ने 1981 से गरीब महिलाओं के साथ कार्य शुरू किया। वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन संगठनों से 6 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं खेती, मछली पालन, फेरी-विक्रय, पोल्ट्री, बुनाई और खाद्य व्यवसाय सहित लगभग 262 प्रकार के कार्यों में सक्रिय हैं।

500 करोड़ रुपये के छोटे ऋण

इन संगठनों द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपये के छोटे ऋण वितरित किए गए हैं। खास बात यह है कि ऋण के साथ महिलाओं को नेतृत्व, वित्तीय जागरूकता, उद्यम विविधीकरण और परिसंपत्ति निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

ऋण से जमीन की मालिक बनी महिला

आजाद ने पद्मावती का उदाहरण देते हुए बताया कि अनाज के रूप में मजदूरी प्राप्त करने वाली एक महिला ने छोटे ऋणों के माध्यम से बैल, कृषि उपकरण और जमीन खरीदी। इसके बाद वह अपनी फसल एवं विपणन संबंधी निर्णय स्वयं लेने लगी। उन्होंने बताया कि इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर विमेन की लगभग 38 प्रतिशत महिला सदस्यों के नाम भूमि का स्वामित्व है।

"Accumulation at Base" मॉडल

आजाद ने इस प्रक्रिया को "Accumulation at Base" मॉडल बताया। इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें परिसंपत्ति स्वामित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता और नेतृत्व तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान 65 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, शाखा प्रबंधकों और महिला नेताओं को डिजिटल लेनदेन, NEFT एवं UPI का प्रशिक्षण दिया गया।

सहकारिता बन सकती है महिला सशक्तिकरण का माध्यम

आजाद ने कहा कि गरीब महिलाओं को यदि वित्त, प्रशिक्षण और उचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो वे सहकारी संस्थाओं एवं अन्य आर्थिक संगठनों का प्रभावी संचालन कर सकती हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को ऋण वितरण से आगे ले जाकर स्वामित्व और नेतृत्व से जोड़ने पर जोर दिया। महिला को केवल ऋण लेने वाली नहीं, बल्कि परिसंपत्ति की मालिक, उद्यमी और निर्णयकर्ता बनाना ही वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण है।

जिला सहकारी संघ राजनांदगांव की 45वीं आमसभा संपन्न

सहकारी प्रशिक्षण देने के लिए भूमि- भवन की मांग

राजनांदगांव। जिला सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव की 45 वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक 30 सितंबर को श्री सौरभ शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी छ.ग. राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर, श्री एन. एल. टण्डन जी उप आयुक्त सहकारिता राजनांदगांव एवं श्री अमलेन्दू हाजरा जी पूर्व लोकपाल एवं सहकारी कार्यकर्ता की उपस्थिति में संपन्न हुई।

श्री सौरभ शर्मा प्राधिकृत अधिकारी छ.ग. राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर ने आमसभा में उपस्थित संघ प्रतिनिधियों को सहकारी समिति की अवधारणा, संदस्यों के लिए सहकारी प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं सहकारी आन्दोलन की मजबूती हेतु राज्य सहकारी संघ एवं जिला सहकारी संघ की भूमिका पर सारगर्भित प्रकाश डालते हुए जिला सहकारी संघो को सहकारी प्रशिक्षण संचालन हेतु भूमि/भवन उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर प्रस्ताव रखे जाने का आश्वाशन दिए।



प्रस्तुत किया गया वार्षिक प्रतिवेदन

श्री एन. एल. टंडन उप आयुक्त सहकारिता ने राजनांदगांव जिले के समस्त पंजीकृत सहकारी समितियों को अधिनियम के प्रावधान अनुसार जिला सहकारी संघ को देय वार्षिक सदस्यता शुल्क एवं अभिदाय राशि भुगतान हेतु निर्देशित किए जाने का आश्वासन दिया। आमसभा में श्री आलोक सिंह प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव द्वारा वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के माध्यम से संघ में समितियों की सदस्यता, संघ की आर्थिक स्थिति, वर्ष में किए गए प्रचार-प्रसार एवं सहकारी शिक्षा-प्रशिक्षण की जानकारी दी।

प्रस्तावित बजट एवं कार्यक्रमों का अनुमोदन

संघ के प्रबंधक श्री एन कुमार साहू ने आमसभा में निर्धारित विषयों को अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु रखा। जिसमें शामिल थे- वर्ष 2025-26 का वित्तीय पत्रक, वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बजट एवं प्रस्तावित कार्यक्रम। उक्त विषयों पर विचार करते हुए सभा ने अवलोकन पश्चात् स्वीकृति दी। पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा सहकारी समितियों के लिए निर्धारित सेवाओं के न्यूनतम स्तर का प्रावधान संघ के पंजीकृत उपविधि में किए जाने का प्रस्ताव रखा गया जिसे आमसभा ने उपविधि में उक्त प्रावधान किए जाने की स्वीकृति दी। संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री आलोक सिंह द्वारा आमसभा में सहकारी शिक्षा-प्रशिक्षण एवं संघ के कार्यालय संचालन हेतु भूमि/भवन की मांग शासन से किए जाने का प्रस्ताव रखा उक्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर विभिन्न सहकारी समितियों के संघ प्रतिनिधिगण, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित थे।



55,514 पैक्स ग्रामीण भारत में डिजिटल सेवाओं का बनेंगे केंद्र



नई दिल्ली। देशभर में 55,514 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में ग्रामीण समुदायों को 300 से अधिक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। सहकारिता मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी साझा की। मंत्रालय के अनुसार, पैक्स के जरिए ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार से जुड़ी सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पैन संबंधी सेवाएं और टिकट बुकिंग जैसी कई महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं मिल रही हैं।

गांवों तक पहुंचेंगी सुविधाएं

ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सुविधा इस पहल का उद्देश्य गांवों में लोगों तक आवश्यक डिजिटल सेवाएं आसानी से पहुंचाना है। पैक्स को सीएससी के रूप में विकसित किए जाने से ग्रामीण नागरिकों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए दूर-दराज के शहरों या कस्बों का रुख नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी सेवाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। इससे समय और यात्रा लागत में भी कमी आ सकती है।



पैक्स की भूमिका होगी मजबूत

पैक्स को डिजिटल सेवा केंद्रों के रूप में मजबूत करने से सहकारी संस्थाओं की भूमिका केवल कृषि ऋण और वित्तीय गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगी। वे ग्रामीण स्तर पर नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी काम करेंगी। सहकारिता मंत्रालय की इस पहल को ग्रामीण डिजिटल समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे ग्रामीण समुदायों को तकनीक आधारित सेवाओं से जोड़ने और डिजिटल भारत अभियान को जमीनी स्तर पर विस्तार देने में मदद मिल सकती है।

खेती बैंक में डिजिटल बैंकिंग की हुई नई शुरुआत



सहकारिता मंत्री जितुभाई वाघाणी ने व्हाट्सऐप और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का किया शुभारंभ

अहमदाबाद। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड ने डिजिटल बैंकिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए व्हाट्सऐप बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। गुजरात के सहकारिता मंत्री जितुभाई वाघाणी ने बैंक मुख्यालय में इन दोनों डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया।

नई सेवाओं के माध्यम से बैंक की सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में पहल की गई है। यह कदम सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैंक मुख्यालय पहुंचने पर अध्यक्ष डॉलर कोटेचा ने सहकारिता मंत्री का स्वागत किया। मंत्री ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बैंक के संस्थापक युवराजश्री उदयभानसिंहजी को श्रद्धांजलि दी।

विकास यात्रा की दिखाई झलक

कार्यक्रम में बैंक की विकास यात्रा, प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी गई। बैंक की कार्यप्रणाली एवं विकास को दर्शाने वाले वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों और अब तक की उपलब्धियों की जानकारी दी।

सहकारी बैंकिंग को डिजिटल गति

व्हाट्सऐप और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत को सहकारी बैंकिंग को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे बैंक और उसके ग्राहकों के बीच डिजिटल संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में बैंक के उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आधुनिक खेती और नवाचार को अपनाएं: निरंजन सिन्हा

पैक्स व लैम्प्स समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों एवं प्रबंधकों के लिए



धमतरी। जिला सहकारी संघ धमतरी द्वारा जिले के पैक्स व लैम्प्स समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों एवं प्रबंधकों का सहकार से समृद्धि के साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक खेती, नवाचार तथा खेती-बाड़ी से जुड़े विषयों पर एकदिवसीय कार्यशाला का बायोजन किया गया।

नवीन प्रशिक्षण हाल डिपो परिसर वन विभाग सिहावा चौक धमतरी में 23 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निरंजन सिन्हा अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती मीना साहू सभापति सहकारिता जिला पंचायत धमतरी, डॉक्टर ईश्वर सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी, सुश्री सुमन ध्रुव सहायक आयुक्त सहकारिता धमतरी के विशिष्ट आतिथ्य एवं कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के डॉक्टर शक्ति वर्मा, डॉक्टर अमित सिन्हा, डॉक्टर प्रेमलाल साहू, सुमन चंद्राकर सहायक मत्स्य अधिकारी, बलरामपुरी गोस्वामी नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धमतरी, डेमू साहू, जिला सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सी पी साहू की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।

सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक अध्यक्ष निरंजन सिन्हा ने कहा कि, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2021 में केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन के पश्चात शासन द्वारा ग्रामीण विकास के साथ कृषकों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने एवं समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। पैक्स को बहुउद्देशीय बनाकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा रासायनिक खाद व दवा का कम उपयोग कर प्राकृतिक व आधुनिक खेती अपनाकर नवाचार को बढ़ाने प्रेरित किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ ईश्वर सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण एवं तकनीक मार्गदर्शन का लाभ लेकर किसान अपनी कृषि आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने फसलों की विविधीकरण एवं समन्वित खेती अपनाने पर जोर देते हुए बताया कि विभिन्न फसलों, दलहन ,तिलहन एवं सब्जियों को शामिल कर किसान अपने परिवार की आवश्यक पोषण संबंधी जरूरतो की पूर्ति अपनी ही उपज से कर सकते हैं। उन्होंने चक्रीय की योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी देते हुए वैज्ञानिक कृषि तकनीको को अपनाने प्रेरित किया।

बताई गई प्राकृतिक खेती की प्रमुख अवधारणाएं

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेमलाल साहू ने किसानों को कम लागत में टिकाऊ एवं लाभकारी खेती करने के लिए प्राकृतिक खेती की प्रमुख अवधारणा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर खेती की लागत को कम किया जा सकता है। इस दौरान किसानों को जीवामृत, धन जीवामृत, जैविक कीट नियंत्रण एवं जैविक कीटनाशक तैयार करने तथा उनके उपयोग की विधि की जानकारी दी। उन्होंने प्राकृतिक खेती में मृदा की जैविक गुणवत्ता एवं लाभकारी सूक्ष्म जीवों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ मिट्टी बेहतर एवं टिकाऊ उत्पादन का आधार है। किसानों को रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक एवं टिकाऊ पद्धति अपनाने अपील की। कृषि प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी वैज्ञानिक डॉ अमित सिन्हा द्वारा कृषकों को नवीनतम कृषि यंत्रों एवं आधुनिक कृषि तकनीक की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती में लगने वाले समय, श्रम एवं लागत को कम किया जा सकता है। किसानों को उन्नत बुवाई यंत्र, आधुनिक कटाई एवं गहाई मशीनों, पावर वीडर, मल्टी क्रोप थ्रेशर तथा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन में उपयोगी विभिन्न यंत्रों की जानकारी दी।

प्रथम पेज का शेष

सहकार से समृद्धि का...

समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें: कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देने का आह्वान करते हुए डॉ. भूटानी ने राज्यों से कार्यशाला के तुरंत बाद अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थाओं की पहचान करने, व्यावहारिक समय-सीमा निर्धारित करने तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि इससे कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श और प्राप्त सुझावों को सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं प्रदर्शन में ठोस सुधारों के रूप में बदला जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई महत्वपूर्ण नवाचार छोटे राज्यों से सामने आए हैं, जिनकी सफल कार्यप्रणालियों को अपनाकर बड़े राज्य भी उल्लेखनीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

नाबार्ड की प्रस्तुति ...

नाबार्ड द्वारा मजबूत और एकरूप कोर बैंकिंग समाधान (CBS) प्लेटफॉर्म विकसित करने के संबंध में दी गई प्रस्तुति की सराहना करते हुए डॉ. भूटानी ने कहा कि इससे कुछ सहकारी बैंकों में उपयोग की जा रही अलग-अलग और अविश्वसनीय तकनीकी प्रणालियों से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के निकट है। आधुनिक और मानकीकृत बैंकिंग प्लेटफॉर्म की उपलब्धता से सहकारी बैंक अन्य बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। उन्होंने साइबर सुरक्षा के साथ इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और विशेष रूप से नई पीढ़ी के युवाओं को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने युवा ग्राहकों को जोड़ने के लिए कुछ सहकारी बैंकों द्वारा की गई पहलों की भी सराहना की।

अनौपचारिक दुग्ध संग्रहण व्यवस्थाओं को संगठित सहकारी ढांचे में लाएं: डेयरी सहकारी संस्थाओं, दुग्ध एकत्रीकरण केंद्रों और मिल्क पूलिंग पॉइंट्स से संबंधित चर्चाओं का उल्लेख करते हुए सचिव ने गांवों में संचालित अनौपचारिक दुग्ध संग्रहण व्यवस्थाओं को संगठित सहकारी ढांचे में लाने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने कहा कि, मदर डेयरी और अमूल जैसी संस्थाओं के लिए गांवों में दूध एकत्र करने वाली व्यवस्थाओं को औपचारिक सहकारी संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि दुग्ध उत्पादकों को सहकारी व्यवस्था का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन में हुई उत्साहजनक प्रगति की सराहना करते हुए इन प्रयासों को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

नई PACS के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश : नई PACS के विस्तार का उल्लेख करते हुए डॉ. भूटानी ने स्वीकार किया कि, राज्यों को नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के गठन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने अगले दो से तीन वर्षों में लगभग 95,000 ऐसी संस्थाओं के गठन के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए मौजूदा PACS के विभाजन, नई समितियों के गठन और सदस्यता विस्तार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया। PACS के लिए उपयुक्त जनसंख्या कवरेज पर नाबार्ड के अध्ययन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्यता बढ़ाने और नई PACS के गठन से सहकारी ऋण वितरण का संस्थागत आधार मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) की व्यवहार्यता के लिए PACS और उनके सदस्यों का पर्याप्त व्यापक नेटवर्क आवश्यक है।

सफल कार्यप्रणालियों की सराहना : सहकारिता सचिव ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और पुडुचेरी सहित विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा साझा की गई सफल कार्यप्रणालियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि, इन अनुभवों से स्पष्ट होता है कि राज्य अपनी विशिष्ट क्षमताओं की पहचान कर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सहकारी विकास के मॉडल तैयार कर रहे हैं। ऐसे मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी उदाहरण बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यशाला की कार्यवाही और बैठक के कार्यवृत्त में ऐसे प्रासंगिक एवं व्यावहारिक मॉडलों की पहचान की जाएगी, जिन्हें अन्य राज्य भी अपनाने पर विचार कर सकें।

PACS कम्प्यूटरीकरण समय पर पूरी करनी होगी: PACS कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ. भूटानी ने कहा कि, यह योजना मंत्रालय की प्रमुख केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित पहलों में शामिल है और राज्यों को सभी लंबित गतिविधियां समय पर पूरी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान योजना मार्च 2027 में समाप्त होने वाली है तथा शेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार के बिना इसकी अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने जोर दिया कि PACS कम्प्यूटरीकरण के पहले चरण के सभी घटक दिसंबर 2026 तक पूरे किए जाएं, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक संपन्न होने चाहिए। उन्होंने कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए खातों का समय पर मिलान करने और अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन रखने की आवश्यकता भी रेखांकित की।

MSP के अतिरिक्त लाभकारी दाम दिलाने वैकल्पिक माडल की तलाश: डॉ. भूटानी ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए वैकल्पिक कृषि विपणन और वित्तपोषण व्यवस्थाएं विकसित करने में विकेंद्रीकृत भंडारण अवसंरचना की संभावनाओं को भी रेखांकित किया। आर्थिक कार्य विभाग के साथ हाल में हुई चर्चाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, मंत्रालय प्लेज फाइनेंस सहित वैकल्पिक मॉडलों की संभावनाएं तलाश रहा है, जिनके लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क आवश्यक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि, इन पहलों का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त टिकाऊ और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे विकल्प विकसित करना है, जिनसे विशेष रूप से गेहूं और धान के अलावा अन्य अनाजों के किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके, जहां स्वक्कआधारित खरीद तक पहुंच में व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं।

चयनित जिलों में पायलट परियोजनाओं पर विचार: सचिव ने कहा कि, मंत्रालय अगले दो से तीन महीनों में ऐसे संभावित मॉडल राज्यों के साथ साझा करने और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक क्रियान्वयन से पहले चयनित जिलों में पायलट परियोजनाएं शुरू करने की संभावनाओं पर विचार करेगा। उन्होंने राज्यों से इन अवसरों का अध्ययन करने तथा किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, स्थानीय कृषि बाजारों को मजबूत बनाने और सहकारी संस्थाओं की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने वाले किसान-केंद्रित मॉडलों के विकास के लिए व्यावहारिक सुझाव देने का आग्रह किया।

डॉ. भूटानी ने प्रदेश सरकार और प्रशासन का जताया आभार: अपने समापन संबोधन में डॉ. भूटानी ने कार्यशाला के सुचारु आयोजन में सहयोग और व्यवस्थाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, बस्तर के कलेक्टर और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श से सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगली राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला जनवरी 2027 में महाबलीपुरम, तमिलनाडु में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

मुलकानूर से कोथाकोंडा...

प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री सौरभ शर्मा, मानसेवी सदस्य एवं सहकार भारती छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री श्री कनीराम शर्मा, श्री के.एन. कांडेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.सी. ध्रुव, श्रीमती स्मिता दोदके, श्रीमती पूजा पांडेय, श्री शशांक बलेवार, श्रीमती नमिता ताम्रकार, श्री पी.एल. सोनी, श्री राजेश कुमार साहू, श्री एस.के. पटेल, श्री एम.एल. दुबे, श्री किरण कुमार ध्रुव, श्री भगबली साहू, श्री अश्वनी कुमार यादव, श्रीमती आराधना वर्मा एवं श्री मितेश पाणिग्रही शामिल थे।



चित्रकोट के प्राकृतिक वैभव और बस्तर की लोक-संस्कृति ने जीता सहकारिता अधिकारियों का दिल

चित्रकोट जलप्रपात पहुंचे देशभर के अधिकारी, गौर नृत्य से हुआ आत्मीय स्वागत

रायपुर। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे देशभर के वरिष्ठ अधिकारियों ने बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति का अनुभव किया। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन के बाद अधिकारियों ने विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात का भ्रमण किया। इंद्रावती नदी की मनोहारी जलधारा और बस्तर की पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

चित्रकोट पहुंचने पर स्थानीय जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक गौर नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। गौर सींगों से सुसज्जित मुकुट, कौड़ियों की मालाएं और पारंपरिक वेशभूषा धारण किए कलाकारों ने मांदर एवं ढोल की थाप पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने कलाकारों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए बस्तर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के महत्व को रेखांकित किया।भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने चित्रकोट जलप्रपात के विभिन्न दृश्यावलोकन स्थलों से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। इस अवसर पर बस्तर की जनजातीय परंपराओं, स्थानीय लोककला और प्राकृतिक संपदा की विशेष रूप से सराहना की गई।



सहकारिता से स्थानीय आजीविका को मिल सकती है नई दिशा

चित्रकोट भ्रमण के दौरान स्थानीय वनोपज, जनजातीय उत्पादों और इको-टूरिज्म को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यापक बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सहकारिता के जरिए स्थानीय उत्पादकों, वनवासी समुदायों और ग्रामीण उद्यमियों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इस अवसर पर भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी, छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता सचिव श्री सी. आर. प्रसन्ना, संभागायुक्त श्री डोमन सिंह, सहकारी संस्थाओं के पंजीयक श्री रमेश शर्मा, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा सहित केंद्र एवं विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के साथ बस्तर की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का यह परिचय छत्तीसगढ़ की पहचान, जनजातीय परंपराओं और सहकारिता आधारित स्थानीय विकास की संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बना।

पुनर्वास से स्वावलंबन तक

'कैफे पण्डुम' बना बस्तर में बदलाव की नई पहचान



सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी ने की सराहना, मुख्यधारा में लौटे युवाओं की उद्यमशीलता को बताया प्रेरक पहल

रायपुर। बस्तर में पुनर्वासित युवाओं द्वारा संचालित 'कैफे पण्डुम' स्वावलंबन, सम्मानजनक आजीविका और सामाजिक बदलाव की प्रेरक मिसाल बनकर उभरा है। भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित केंद्र और विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने जगदलपुर स्थित कैफे का भ्रमण कर इस पहल की सराहना की।

कैफे भ्रमण के दौरान बस्तर के कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने अधिकारियों को कैफे की स्थापना की अवधारणा, संचालन और इससे जुड़े परिवारों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं को रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है।

स्थानीय पहल, सामाजिक बदलाव का संदेश

कैफे की सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं, आत्मीय आतिथ्य और स्थानीय परिवेश के अनुरूप विकसित परिसर ने अधिकारियों को प्रभावित किया। प्राकृतिक रंगों से सजे वातावरण और स्थानीय व्यंजनों की भी उन्होंने प्रशंसा की। अधिकारियों ने कैफे का संचालन कर रहे युवाओं से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया।

राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली सराहना ने कैफे संचालकों का मनोबल बढ़ाया। यह पहल बताती है कि पुनर्वास के साथ रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराकर युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। इससे समाज में विश्वास, सकारात्मकता और विकास की नई संभावनाएं भी विकसित होती हैं।

आजीविका के माध्यम से सशक्तीकरण

'कैफे पण्डुम' जैसी पहल बस्तर में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और सामाजिक पुनर्स्थापन की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देती है। ऐसे प्रयासों को सहकारी संस्थाओं, स्थानीय उद्यमों और आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों से जोड़कर व्यापक स्तर पर विकसित किया जा सकता है, जिससे अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलें।

उल्लेखनीय है कि डॉ. आशीष भूटानी सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन 'सहकार से समृद्धि' में शामिल होने पहुंचे थे। सम्मेलन के दौरान बस्तर की विकास संभावनाओं और स्थानीय पहलों से परिचित होने का अवसर भी मिला।

सहकारिता को मिलेगी नई गति

2-3 वर्षों में 95 हजार नई पैक्स बनाने का लक्ष्य

डॉ. आशीष भूटानी ने राज्यों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश; डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और ग्रामीण भंडारण पर जोर



अगला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन जनवरी 2027 में महाबलीपुरम में होगा

रायपुर। देश में सहकारिता आंदोलन को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए राज्यों को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करनी होगी। सहकारिता के विकास के लिए पूरे देश में एक ही मॉडल अपनाने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाना जरूरी है। भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी ने यह बात बस्तर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन 'सहकार से समृद्धि' के समापन सत्र में कही।

डॉ. भूटानी ने कहा कि सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श को ठोस कार्ययोजना में बदलना और उसके क्रियान्वयन की समयबद्ध समीक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने आगामी दो से तीन वर्षों में लगभग 95 हजार नई प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के गठन के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे ग्राम स्तर पर सहकारिता का विस्तार होगा। साथ ही, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिरता के लिए पैक्स का सक्रिय, सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है।

सहकारी उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और सहकारी उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए डॉ. भूटानी ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के बीच तालमेल से किसानों और प्राथमिक समितियों के लिए कारोबार के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान

सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने नाबार्ड द्वारा विकसित किए जा रहे एकीकृत कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तकनीकी उन्नयन से सहकारी बैंकों की सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा को मजबूत करने तथा वित्तीय जोखिमों से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है।

उन्होंने पैक्स कंप्यूटरीकरण के पहले चरण को दिसंबर तक पूरा करने और लंबित ऑडिट कार्यों को अक्टूबर तक निपटाने पर भी जोर दिया। इससे सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भंडारण और डेयरी सहकारिता के विस्तार की जरूरत

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए डॉ. भूटानी ने देशव्यापी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के साथ-साथ टिकाऊ स्थानीय विपणन विकल्प विकसित करना भी जरूरी है। ताकि उन्हें अपनी उपज के बेहतर बाजार मिल सकें।उन्होंने गांवों में असंगठित दुग्ध संकलन केंद्रों को औपचारिक डेयरी सहकारी समितियों में परिवर्तित करने की आवश्यकता भी रेखांकित की। इससे दुग्ध उत्पादकों को संगठित बाजार, बेहतर सेवाओं और सहकारी व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।

मुलकानूर की सफल सहकारी व्यवस्था का अध्ययन करने वारंगल पहुंचा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल

मुलकानूर सहकारी संस्था के अध्यक्ष प्रदीप रेड्डी से की मुलाकात, दुग्ध सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के मॉडल को समझा





रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के वारंगल जिले के मुलकानूर में सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, ग्रामीण आर्थिक विकास और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन किया। तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण के अंतर्गत प्रतिनिधिमंडल ने 12 अक्टूबर को मुलकानूर स्थित सहकारी संस्थाओं का दौरा किया और वहां की सफल सहकारी व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।

अध्ययन भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुलकानूर सहकारी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रदीप रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान सहकारी संस्था के संचालन, सदस्यों की भागीदारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सहकारिता के माध्यम से स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने से जुड़े विषयों पर जानकारी प्राप्त की गई।

दुग्ध सहकारिता से महिला सशक्तीकरण की पहल

प्रतिनिधिमंडल ने मुलकानूर वुमेन्स कोऑपरेटिव डेयरी से संबंधित संस्था का भी भ्रमण किया। यहां महिला सदस्यों की भागीदारी, दुग्ध उत्पादन एवं संकलन, सहकारी गतिविधियों और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी ली गई। प्रतिनिधिमंडल ने जाना कि संगठित सहकारी व्यवस्था महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, सामूहिक भागीदारी बढ़ाने और आर्थिक निर्णयों में उनकी भूमिका मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। दुग्ध सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को एकजुट कर स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर विकसित करने का यह अनुभव छत्तीसगढ़ की सहकारी संस्थाओं के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

छत्तीसगढ़ में सहकारिता को मजबूत बनाने की दिशा में अध्ययन

इस अध्ययन भ्रमण का उद्देश्य तेलंगाना की सफल सहकारी संस्थाओं के अनुभवों से सीख लेकर छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता, सदस्य सहभागिता, आजीविका संवर्धन और प्रशिक्षण गतिविधियों को बेहतर बनाने की संभावनाओं को समझना है। मुलकानूर की सहकारी व्यवस्था का अध्ययन राज्य की प्राथमिक सहकारी समितियों, दुग्ध सहकारी संस्थाओं और महिला सहकारी संगठनों के लिए उपयोगी अनुभव प्रदान कर सकता है। प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के अध्यक्ष श्री सौरभ शर्मा, मानसेवी सदस्य एवं सहकार भारती छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री श्री कनीराम शर्मा, अपर पंजीयक सहकारिता एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंध संचालक श्री के.एन. कांडेय, संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.सी. ध्रुव सहित सहकारी क्षेत्र के पदाधिकारी, अधिकारी और सहकारी प्रशिक्षण केंद्र रायपुर एवं जगदलपुर के व्याख्याता शामिल थे। इस भ्रमण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थाओं के विकास, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों और कार्यपद्धतियों को अपनाने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

महिला थ्रिफ्ट सहकारिता के सफल मॉडल से रूबरू हुआ छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल





CDF कोथाकोंडा में महिला सहकारी संस्थाओं का अध्ययन, WTC और U AWTC के प्रतिनिधियों से किया संवाद

कोथाकोंडा- तेलंगाना। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपने तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण के अंतिम दिन कोथाकोंडा स्थित कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन (CDF) के अंतर्गत संचालित महिला थ्रिफ्ट सहकारी संस्थाओं का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने महिला थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव (WTC) तथा एसोसिएशन ऑफ वुमेन थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव (AWTC) के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी कार्यप्रणाली और महिला सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त की।

बचत और ऋण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने महिला थ्रिफ्ट सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। चर्चा में महिलाओं को सहकारिता से जोड़ने, नियमित बचत की आदत विकसित करने, आवश्यकता के समय ऋण सुविधा उपलब्ध कराने तथा सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने जैसे विषयों की जानकारी ली गई।महिला थ्रिफ्ट सहकारी संस्थाओं का यह मॉडल महिलाओं को संगठित कर उनमें वित्तीय अनुशासन, आपसी सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी संस्थाएं महिलाओं को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए संगठित व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देती हैं।

सहकारी संस्थाओं के अनुभवों का किया आदान-प्रदान: प्रतिनिधिमंडल ने WTC और AWTC के प्रतिनिधियों से संस्था संचालन, सदस्य सहभागिता तथा महिला सहकारी संगठनों की भूमिका से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

वारंगल डीसीसीबी की कार्यप्रणाली से रूबरू हुआ छत्तीसगढ़ का सहकारी प्रतिनिधिमंडल

वारंगल। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के वारंगल में अपने तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण के दूसरे दिन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था और बैंक के कामकाज से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

डीसीसीबी के अधिकारियों से की चर्चा: अध्ययन भ्रमण की शुरुआत प्रतिनिधिमंडल ने वारंगल स्थित मां भद्रकाली मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने वारंगल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का दौरा किया। यहां बैंक के एमडी श्री वजीर सुल्तान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जी.वी. उषा श्री तथा उप महाप्रबंधक श्री जे. अशोक से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बैंक की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था और सहकारी बैंकिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। इस संवाद का उद्देश्य वारंगल की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के अनुभवों को समझना और छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों एवं समितियों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी जानकारी हासिल करना था।

सहकारी बैंकिंग के अनुभवों से सीखने का अवसर: अध्ययन भ्रमण के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल को दूसरे राज्य की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को नजदीक से समझने का अवसर मिला।



वारंगल में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने किए मां भद्रकाली के दर्शन, जिला सहकारी बैंक का भी किया अध्ययन



अध्ययन

रामप्पा मंदिर की ऐतिहासिक विरासत से हुए रूबरू, तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण के दूसरे दिन धार्मिक, सहकारी और सांस्कृतिक स्थलों का किया दौरा

वारंगल। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के वारंगल में तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण के दूसरे दिन धार्मिक, सहकारी और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। दिन की शुरुआत प्रतिनिधिमंडल ने प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का दौरा कर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के अंतिम चरण में सदस्यों ने विश्वप्रसिद्ध रामप्पा मंदिर के दर्शन कर क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं स्थापत्य विरासत का अवलोकन किया।

मां भद्रकाली मंदिर में किए दर्शन

अध्ययन भ्रमण के दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने सुबह वारंगल स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर पहुंचकर पूजा- अर्चना की। मंदिर की धार्मिक महत्ता और शांत वातावरण के बीच सदस्यों ने प्रदेश की सुख-समृद्धि तथा सहकारिता आंदोलन की प्रगति की कामना की।



रामप्पा मंदिर की ऐतिहासिक विरासत से हुए परिचित

दिन के अगले पड़ाव में प्रतिनिधिमंडल ने रामप्पा मंदिर का भ्रमण किया। अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। सदस्यों ने मंदिर की वास्तुकला और ऐतिहासिक विशेषताओं का अवलोकन किया।

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का किया भ्रमण

धार्मिक दर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का दौरा किया। इस दौरान सहकारी बैंकिंग व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की भूमिका तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों और सदस्यों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने जैसे विषयों को समझने का अवसर मिला। सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वित्तीय आधार देने और प्राथमिक सहकारी समितियों को सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अध्ययन भ्रमण से अनुभवों का आदान-प्रदान

छत्तीसगढ़ के सहकारी प्रतिनिधिमंडल का यह अध्ययन भ्रमण सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझने के साथ- साथ विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से परिचित होने का अवसर भी बना।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक विवेकानंद झा द्वारा क्वालिटी आफसेट, पुरानी बस्ती, रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcoop.in E-mail- cgcoopnews@gmail.com